

UPPCS

21 January, 2025

प्रश्न-1. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, इसके विकास में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों की भूमिका को रेखांकित करें। (125 शब्द)

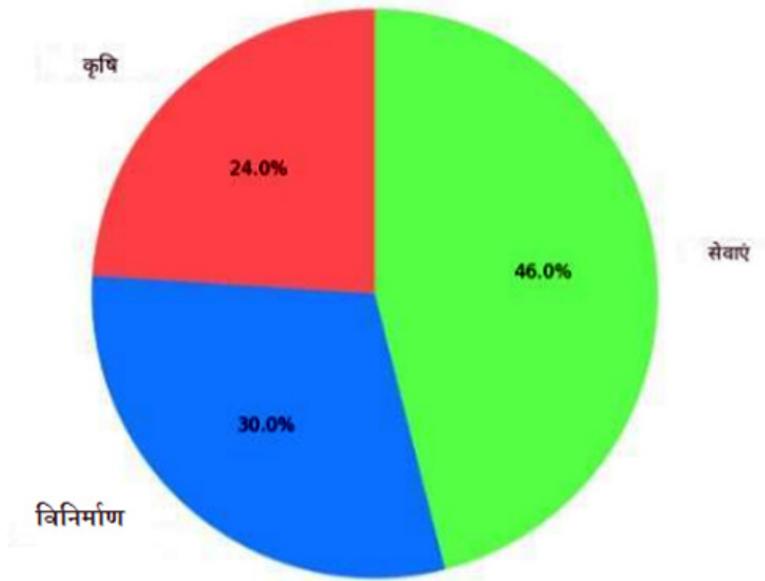
उत्तर:

भूमिका

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला तथा एक विविध अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं (300 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य)

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान (\$300 बिलियन)



- कृषि:** उत्तर प्रदेश गेहूँ और गन्ने का प्रमुख उत्पादक है, जो राज्य की जीडीपी में 24% योगदान करता है। राज्य भारत के चावल उत्पादन के 17% का भागीदार है और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उद्योग:** विनिर्माण क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 30% योगदान करता है, जिसमें वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में वृद्धि हो रही है। प्रमुख औद्योगिक हब में आगरा, कानपुर, नोएडा शामिल हैं।
- सेवाएं:** सेवा क्षेत्र, जिसमें आईटी और शिक्षा शामिल हैं, राज्य की जीडीपी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो 46% है। नोएडा एक महत्वपूर्ण आईटी और व्यापार आउटसोर्सिंग हब है, जो राज्य के आर्थिक विस्तार में मदद करता है।

बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों की भूमिका

- बुनियादी ढांचा:** उत्तर प्रदेश की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और समर्पित मालवाहन गलियारा, व्यापार और संपर्क को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लखनऊ और वाराणसी में एयरपोर्ट भी राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाते हैं। (6 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट)
- भौतिक संसाधन:** उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है, जो कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक है, तथा चूना पत्थर और रेत जैसे खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जल संसाधन विशेष रूप से राज्य के पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत कृषि आधार, बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र, और तेजी से विस्तार करने वाले सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित है। बुनियादी ढांचे और संसाधन प्रबंधन में व्यापक निवेश के साथ राज्य निरंतर विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए तैयार है।

UPPCS

21 January, 2025

प्रश्न-2. उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें, और विश्लेषण करें कि यह राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बढ़ावा दे सकती है और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या भूमिका निभा सकती है। (200 शब्द)

उत्तर:

भूमिका:

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 एक रणनीतिक पहल है, जो राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह नीति भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है तथा धारणीयता और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देती है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

- उत्पादन लक्ष्य:** उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2028 तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया का उत्पादन प्राप्त करना है, जिससे हरित ऊर्जा में अग्रणी बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
- उत्कृष्टता केंद्र:** नीति के तहत 4 उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) की स्थापना की जाएगी, जो ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र के विकास में शोध, प्रौद्योगिकी नवाचार, और विकास का समर्थन करेंगे।
- मांग और खपत:** राज्य में पहले से 0.9 मिलियन मीट्रिक टन की हाइड्रोजन की मांग है, जो मुख्य रूप से उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्रों में उपयोग होती है। यह नीति इस मांग को घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखती है।

औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा:

- ग्रीन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि:** 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य, ग्रीन ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे उर्वरक और रिफाइनिंग जैसे प्रमुख हाइड्रोजन उपभोक्ता उद्योगों को समर्थन मिलेगा।
- निवेश आकर्षित करना:** पूंजी सब्सिडी, भूमि प्रोत्साहन, और बिजली आपूर्ति लाभ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं और संबंधित उद्योगों में निवेश को आकर्षित करेंगे, जिससे नवाचार और रोजगार सृजन होगा।

ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना:

- सतत ऊर्जा आपूर्ति:** यह नीति हाइड्रोजन उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करती है। पहले 10 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क छूट हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए लागत प्रभावी ऊर्जा सुनिश्चित करती है।
- हाइड्रोजन मांग को पूरा करना:** उर्वरक और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में 0.9 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने से बाह्य स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा स्वच्छता में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

यह नीति औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है और एक ग्रीन ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है, साथ ही निवेश को आकर्षित करती है और सतत ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करती है। यह राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप है।

UPPCS

21 January, 2025

प्रश्न-3. मानव संसाधन और कौशल विकास पर विशेष जोर देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं के लोगों के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर:

भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं, विशेष रूप से मानव संसाधन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पहलें रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

मुख्य कल्याणकारी योजनाएं:

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** यह मृतक आय कमाने वाले सदस्य के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो संकटपूर्ण समय में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- कुष्ठ पेंशन योजना:** कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को मासिक पेंशन देती है, जिससे वित्तीय स्थिरता और जीवन स्तर में सुधार होता है।
- विवाह प्रोत्साहन योजना:** आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी भलाई के लिए मदद मिलती है।
- दिव्यांगजन के लिए मुफ्त मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गतिशीलता का समर्थन करती है, जिससे समावेशिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

कौशल विकास पहलें

- राज्य कौशल विकास कोष (IWF):** यह कौशल विकास कार्यक्रमों को समर्थन देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि युवा रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करें।
- STEP-UP (गरीबों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण):** यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) योजना की एक घटक है, जो शहरी गरीबों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।
- मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना:** राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन:** यह योजना युवा कौशल को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से निर्माण, आईटी, और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में, और 1.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर चुकी है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** केंद्र सरकार के सहयोग से, यह योजना विभिन्न व्यापारों में लघु अवधि प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA):** यह योजना हर साल एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करती है और परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है।
- एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण (पीएम-विश्वकर्मा योजना):** पारंपरिक कारीगरों को उनके कौशल और उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने में समर्थन करती है, जिससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं ने नागरिकों की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से कौशल विकास और मानव संसाधन के क्षेत्र में। इन पहलों ने बेहतर रोजगार अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है।

UPPCS

21 January, 2025

प्रश्न-4. उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं?
(125 शब्द)

उत्तर:

भूमिका

उत्तर प्रदेश 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, हालांकि इसे कई महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी आर्थिक क्षमता को प्रभावित करते हैं।

निवेश से संबंधित प्रमुख समस्याएं:

- ❖ **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क बाजारों और संसाधनों तक सुगम पहुंच को सीमित करते हैं। मजबूत बिजली आपूर्ति और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी निवेश को हतोत्साहित करती है।
- ❖ **भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां:** जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और बार-बार होने वाले भूमि विवाद औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में देरी का कारण बनते हैं।
- ❖ **कौशल अंतर:** बड़े श्रमिक बल के बावजूद, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल अंतर है, जो रोजगार सृजन और औद्योगिक वृद्धि को प्रतिबंधित करते हैं।
- ❖ **नीति में असंगतताएं:** बार-बार होने वाले नीति परिवर्तन और अस्पष्ट नियम निवेशकों में असमंजस पैदा करते हैं और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को रोकते हैं।

आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव

ये समस्याएं औद्योगिक विस्तार को सीमित करती हैं और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती हैं, जिससे रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति में धीमापन आता है। हालांकि, उत्तर प्रदेश निवेश नीति 2022 और राज्य कौशल विकास फंड जैसी योजनाएं अवसंरचना में सुधार और कौशल अंतर को पाटने का प्रयास करती हैं, जिससे भविष्य में आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने, औद्योगिकीकरण को तेज करने और सतत आर्थिक वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना की खामियों, भूमि अधिग्रहण चुनौतियों और कौशल विकास को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।